

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (III) 2021 का तीसरा संस्करण

सिलेबस: जीएस पेपर-III (नीति आयोग, विकास और विकास)

भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2021 नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग द्वारा जारी की गई थी जिसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा था।

यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ढांचे को रेखांकित करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को उजागर करता है।

संकेतकों की संख्या 36 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में) से बढ़कर 66 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में) हो गई है।

भारत नवाचार सूचकांक के बारे में

- यह एक व्यापक उपकरण है जिसे नीति आयोग द्वारा देश के अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए प्रतिस्पर्धा संस्थान के साथ विकसित किया गया है।
- यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है।
- सूचकांक में 7 स्तंभ हैं - पांच 'Enabler' स्तंभ इनपुट को मापते हैं और दो 'प्रदर्शन' स्तंभ आउटपुट को मापते हैं।

- सर्वेक्षण जिन संकेतकों का उपयोग करता है, उनमें शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता और पैरामीटर शामिल हैं जैसे:

1. पीएचडी छात्रों की संख्या और ज्ञान-गहन रोजगार।
2. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नामांकन और अत्यधिक कुशल पेशेवरों की संख्या।
3. अनुसंधान और विकास में निवेश और पेटेंट और ट्रेडमार्क दायर आवेदनों की संख्या।
4. इंटरनेट ग्राहकों।
5. एफडीआई प्रवाह, व्यापार वातावरण और सुरक्षा और कानूनी वातावरण।



रिपोर्ट की मुख्य बातें

- नीति आयोग के तीसरे भारत नवाचार सूचकांक में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में, कर्नाटक 18.01 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर है।
- प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 14.22 अंकों के साथ 7वें स्थान पर, ओडिशा 11.42 अंकों के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंकों के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर है।
- मणिपुर 19.37 अंकों के साथ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। उत्तराखंड (17.67 अंक) इस वर्ग में दूसरे स्थान पर है, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे नीचे है। दूसरी ओर, केंद्र शासित प्रदेशों और शहर-राज्यों की श्रेणी में, चंडीगढ़ (27.88 अंक) शीर्ष स्थान पर है, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) अंतिम स्थान पर था।

अर्थ

- यह नीति निर्माताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों को **भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिक गतिशीलता का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।**
- यह उन चुनौतियों की पहचान करता है जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अभिनव क्षमताओं को अधिकतम करने और उन्हें संबोधित करने के लिए समाधान प्रदान करने में बनी रहती हैं।

हिमाचल के क्षेत्र में पूरी आबादी को मिल सकता है एसटी टैग

सिलेबस: जीएस पेपर-I और II (सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सामाजिक सशक्तिकरण)

बताया जाता है कि केंद्र हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र को "आदिवासी" का दर्जा देने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है, तो निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करेगा।



भारत में अनुसूचित जनजातियाँ

- 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104 मिलियन है जो देश की आबादी का 8.6% प्रतिनिधित्व करती है।
- संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं।

अनुच्छेद 342 कहता है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से घोषित किया गया है, वे अनुसूचित जनजाति होंगे।

जु अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है और एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

- संविधान अनुसूचित जनजाति के रूप में एक समुदाय के विनिर्देशन के मानदंडों के बारे में चुप है।
- आदिमता, भौगोलिक अलगाव, शर्म, और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन एक-एक लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं।

देश में आदिवासियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 15 (4): अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं);
- अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का पी सङ्गंध (इसमें एसटी शामिल हैं);
- अनुच्छेद 46: राज्य विशेष सावधानी के साथ, लोगों के कमजोर वर्गों, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से बचाएगा;
- अनुच्छेद 350A: मातृभाषा में निर्देश
- अनुच्छेद 350बी: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी;

सामाजिक सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 23: मनुष्यों और भिखारियों और मजबूर श्रम के अन्य समान रूपों में यातायात का निषेध;
- अनुच्छेद 24: बाल श्रम को मना करना.

आर्थिक सुरक्षा उपाय:

- **अनुच्छेद 244:** पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे जो छठी अनुसूची के तहत कवर किए गए हैं;
- **अनुच्छेद 275 संविधान** की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत कवर किए गए विनिर्दिष्ट राज्यों (एसटी एंड एसए) को सहायता अनुदान।

राजनीतिक सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 330: लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;
- **अनुच्छेद 332:** राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण;
- अनुच्छेद 334: आरक्षण के लिए 10 साल की अवधि (अवधि का विस्तार करने के लिए कई बार संशोधित किया गया है।
- अनुच्छेद 243D: पंचायतों में सीटों का आरक्षण;
- **अनुच्छेद 371:** महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान।

HATTI समुदाय के बारे में

- Hattis एक **करीबी बुना समुदाय है जो शहरों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में घर की खेती की सब्जियों, फसलों, मांस, और ऊन आदि को बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम मिला है।**
- हट्टी समुदाय, जिसके पुरुष समारोहों के दौरान एक विशिष्ट सफेद हेडगियर पहनते हैं, **सिरमौर से गिरी और टोंस नामक दो नदियों से कट जाता है। टोंस इसे उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से विभाजित करता है।**
- उत्तराखंड में ट्रांस-गिरि क्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी एक बार 1815 में जौनसार बावर के अलगाव तक सिरमौर की शाही संपत्ति का हिस्सा थे।
- स्थलाकृतिक नुकसान के कारण, **कामराऊ, संग्राहा और शिलुआई क्षेत्रों में रहने वाले हट्टी शिक्षा और रोजगार में पिछड़ जाते हैं।**

आदिवासी दर्जे की मांग

- समुदाय 1967 से मांग कर रहा है, जब जौनसार बावर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनजातीय दर्जा दिया गया था।
- 1967 में, उनके परिवार के सदस्य जो जौनसार में थे, उन्हें आदिवासी घोषित किया गया था, लेकिन जो लोग हिमाचल में रहे, उन्हें समान दर्जा या लाभ नहीं दिया गया था।
- मार्च 2022 में, राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत नृवंशविज्ञान प्रस्ताव भेजा, जिसमें ट्रांस-गिरि क्षेत्र के हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश की एसटी सूची में शामिल करने की मांग की गई थी।

प्रारंभिक परीक्षा मुख्य तथ्य

सेरोटोनिन

- यह एक **मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है जो संचार के लिए एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे में संदेश या संकेतों को संचारित करने में मदद करता है।**
- सेरोटोनिन **नींद, पाचन, भूख, स्मृति और सीखने की क्षमता को विनियमित करने के लिए हार्मोन आर एस्पेन्सिबल है।** इसके अलावा, सेरोटोनिन **मूड संतुलन बनाए रखने से संबंधित है।**
- डी **दमन से पीड़ित व्यक्तियों को सेरोटोनिन के निम्न स्तर से जोड़ा गया है।**
- एक नए अध्ययन से पता चलता है कि अवसाद सेरोटोनिन के कारण नहीं होता है।

सम्राट तितली

International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ने पहली बार प्रवासी सम्राट तितली को **खतरे वाली प्रजातियों की अपनी "लाल सूची" में जोड़ा और इसे "लुप्तप्राय" के रूप में वर्गीकृत किया।**

- सम्राट तितली ग्रह पर सबसे अधिक पहचानने योग्य और अच्छी तरह से अध्ययन तितलियों में से एक है।
- मोनार्क तितलियां **उत्तर और दक्षिण अमेरिका** के मूल निवासी हैं, लेकिन वे अन्य गर्म स्थानों पर फैल गए हैं जहां मिल्कवीड बढ़ता है।
- **खतरे:** निवास स्थान का नुकसान, कृषि के लिए जड़ी-बूटियों और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ना, और जलवायु परिवर्तन।
- **वसूली के लिए आगे का रास्ता:** मिल्कवीड लगाना, एक पौधा जिस पर कैटरपिलर निर्भर करते हैं।

KALI BEIN

- यह एक 165 किलोमीटर का नाला है जो होशियारपुर से शुरू होता है और कपूरथला में ब्यास और सतलुज नदियों के संगम से मिलता है।
- इसे काली बीन (काला नाला) कहा जाता है क्योंकि लगभग 80 गांवों और आधा दर्जन छोटे और बड़े शहरों से औद्योगिक अपशिष्ट इसमें प्रवाहित होता है।